

मुकदमों का विवरण

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी.

हरियाणा राज्य

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 1076-1077) अगस्त 08, 2023

[सी. टी. रविकुमार और संजय कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: अपीलार्थी-अभियुक्त यू/एस. एस. की दोषसिद्धि। 201, 300, 302, आई. पी. सी. आर/डब्ल्यू. एस. 34 परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, जिसमें अंतिम बार देखे गए साक्ष्य, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, अवैध हथियार की बरामदगी और उद्देश्य, यदि न्यायसंगत हो।

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-जब न्यायसंगत नहीं होता है तो उस पर आधारित दोषसिद्धि:

आयोजित किया गया: अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही की सराहना पर निचली अदालतों का स्पष्ट निर्णय यह है कि किसी भी गवाह ने मृतक को आरोपी के साथ जीवित और एक साथ देखने की बात नहीं की थी-इस प्रकार, यह मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि 'अंतिम बार देखे गए साक्ष्य' तत्काल मामले में अपीलकर्ताओं के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में उपलब्ध है-इस तरह के स्पष्ट तथ्य के बावजूद, निचली अदालत ने कुछ अन्य परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए कटववाला मार्ग के पास चारा कक्ष में अपीलकर्ताओं के साथ मृतक की उपस्थिति का अनुमान लगाया-निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी पूरी तरह से विकृत तरीके से साक्ष्य की सराहना की-प्रत्येक मामले में अंतिम निर्णय को देखते हुए। 201, 300 और 303 आर/डब्ल्यू एस। 34, आई. पी. सी.-वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया-अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

861

[अनुच्छेद 12, 13 और 42] 862 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-अंतिम बार देखा गया सिद्धांत-घटना से ठीक पहले अभियुक्त के साथ मृतक की उपस्थिति के बारे में अनुमान, अभियोजन पक्ष के गवाहों के सकारात्मक नेत्र साक्ष्य के अभाव में कि उन्होंने मृतक को अभियुक्त की संगति में एक साथ और घटना के निकट समय में जीवित देखा था-अनिवार्यता:

आयोजित किया गया: 'परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में अंतिम बार देखे जाने पर, यह स्थापित करने के लिए कम से कम एक गवाह की मौखिक गवाही के अस्तित्व का सुझाव मिलेगा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था-किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में 'अंतिम बार देखा गया' के सिद्धांत का अनुप्रयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था, खतरनाक होगा-इसका अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग भी अस्वीकार्य है-वर्तमान मामले में, पीडब्लू-10 का साक्ष्य संदेह से मुक्त नहीं है और किसी भी तरह से, इसे 'अंतिम बार देखा गया' के सिद्धांत के अनुप्रयोग को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सकारात्मक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है या 25.06.1999 की शाम को अपीलार्थियों की कंपनी में मृतक की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए इसे 'अंतिम बार देखा गया' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। [पैरा 8, 21 और 25]

साक्ष्य-उद्देश्य-साबित नहीं किया गया/असंवेदनशील माना गया-गवाहों के साक्ष्य की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए:

आयोजित किया गया: अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और यह सभी संभावनाओं में, प्रत्येक स्वैच्छिक कार्य के पीछे मौजूद होना चाहिए-जब अभियोजन पक्ष एक उद्देश्य के साथ सामने आता है और उद्देश्य या तो साबित नहीं होता है या इसे अनुचित नहीं माना जाता है, तो उक्त तथ्य के गवाहों के साक्ष्य की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। [पैरा 31 और 33]

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-प्रेरक-जब साबित नहीं होता है:

आयोजित किया गया:प्रारंभ में, पीडब्लू-9 (मृतक के भाई) ने एक ऐसी घटना का सुझाव दिया जो 29.05.1999 पर हुई थी, जब उसके पिता और मृत भाई पर हमला किया गया था, लेकिन मृतक भागने में सफल रहा था-लेकिन अपीलकर्ताओं को उस घटना के संबंध में हमलावरों के रूप में नामित नहीं किया गया था-यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह एक उद्देश्य कैसे हो सकता है-अपीलकर्ताओं को भी संदिग्ध अपहरणकर्ताओं/अपहरणकर्ताओं में शामिल नहीं किया गया है-इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ पेश किया गया उद्देश्य यह था कि उन्होंने अपनी बहन ('पी') को कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष में 25.06.1999 की शाम को मृतक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया-हालांकि, किसी भी गवाह के पास 863 नहीं थे

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी.हरियाणा राज्य 864

यहाँ तक कि अपीलकर्ताओं की बहन और मृतक को संबंधित समय पर कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष के अंदर या उपरोक्त स्थान के निकट किसी भी समय देखने की बात की गई-इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया कि 'पी' वास्तव में अपीलकर्ताओं की बहन थी या उनमें से कम से कम एक थी-इस प्रकार, वे भाई-बहन नहीं हैं और फिर, सवाल यह है कि उनके बीच खून की निकटता क्या है-इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था और उस पहलू पर भी अभियोजन पक्ष केवल पीडब्लू-7 के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर निर्भर करता है जो विश्वास को प्रेरित नहीं करता है-अभियोजन पक्ष ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।[पैरा 30 और 33]

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-प्रेरक-महत्वपूर्ण तथ्य:

आयोजित किया गया:परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य का महत्व होता है, लेकिन यह कहने का कोई कारण नहीं है कि उद्देश्य के अभाव में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।[पैरा 33]

दंड संहिता, 1860 -s.364 r/ws।34 - अपीलार्थियों के विरुद्ध बनाए गए आरोप:

आयोजित किया गया:एस में प्रयुक्त वाक्यांश 'सामान्य इरादा'।34 एक पूर्व-व्यवस्थित योजना का तात्पर्य है और योजना के अनुरूप कार्य करना-एक गैर-योजना स्थापित करना।364 यह साबित किया जाना चाहिए कि हत्या के लिए अपहरण या अपहरण के समय आरोपी व्यक्ति का इरादा था या हत्या के खतरे में डालने के लिए निपटाने का इरादा था-अभियोजन पक्ष का मामला, प्रथम आरोप के अनुसार, यह था कि अपीलकर्ताओं ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए मृतक को उसकी हत्या करने के लिए अपहरण कर लिया था-हालांकि एक विशिष्ट आरोप यू/एस के तहत तैयार किया गया था।364 आर/डब्ल्यू एस।34, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं चुना था और वस्तुतः इस तरह के मामले को छोड़ दिया था-पीडब्लू 7 से 10 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, एक पूरी तरह से अलग मामला विकसित किया गया था और अंतिम बार देखे गए साक्ष्य, हथियार की बरामदगी के आधार पर साबित करने का प्रयास किया गया था।, चुन्नी, मकसद और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

- हत्या करने के लिए अपहरण/अपहरण करने के सामान्य इरादे के आधार पर एक पूर्व-व्यवस्थित योजना के आरोप वाले मामले को अपीलार्थियों की बहन को कथित रूप से मृत व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर पल भर में हुए उद्देश्य के आधार पर हत्या के मामले में बदल दिया गया था-अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ बनाए गए आरोप को स्थापित करने की परवाह नहीं की थी।364/34 और इसके बावजूद इसने एक और मामला आगे बढ़ाया।[पैरा 15,16 और 18]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -एस. 60-पीडब्लू-10 के साक्ष्य की प्रयोज्यता, यदि स्वीकार्य हो:

आयोजित किया गया:एस. 60 में कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में प्रत्यक्ष होना चाहिए-हालांकि, यह केवल तभी स्वीकार्य है जब यह कथन की सच्चाई को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों द्वारा बयान के तथ्य को नहीं-अन्य व्यक्तियों द्वारा बयान के तथ्य को साबित करने और इस तरह के कथन की सच्चाई को साबित करने के बीच कोई अंतर नहीं है-वर्तमान मामले में, पीडब्लू-10 ने केवल मृतक के इस तथ्य के बारे में बात की थी कि वह 'पी' से प्यार करता है और कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष में 25.06.1999 की शाम को उससे मिलने के उसके वादे के बारे में भी बात की थी-इसके

अलावा, तथ्य यह है कि हालांकि उसने गवाही दी थी कि उसने अपीलकर्ताओं को लगभग 08.30 बजे देखा था⁶⁰, भले ही यह माना जाए कि पीडब्लू-10 का साक्ष्य इस हद तक स्वीकार्य है कि मृतक ने पीडब्लू-10 को 25.06.1999 की शाम को 'पी' के साथ अपने प्यार और मृतक से मिलने के अपने वादे के बारे में खुलासा किया, पीडब्लू-10 के साक्ष्य को स्वीकार्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है जैसा कि उक्त कथन की सच्चाई से संबंधित है।[पैरा 23 और 24]

साक्ष्य-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, जो कथित रूप से अपीलार्थियों द्वारा पीडब्लू-7 को दी गई थी-स्वीकार्यता:

आयोजित किया गया:अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को हमेशा साक्ष्य के एक कमजोर टुकड़े के रूप में नहीं लिया जा सकता है और यह सवाल कि क्या इसे स्वीकार्य के रूप में लिया जाना और आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि के लिए आधार बनाना योग्य है, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करेगा जिसे कथित रूप से स्वीकारोक्ति दी गई थी-वर्तमान मामले में, अभिलेखों से सामने आए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिन पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर पीडब्लू-7 का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं कर सकता था।[पारस 34 और 40] 865

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी.

साक्ष्य-हथियार की बरामदगी।, गला घोटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चुन्नी

आयोजित किया गया:बरामदगी का स्थान एक खुला स्थान था और सभी के लिए सुलभ था-पीडब्लू-6 और पीडब्लू-14 के बयान के साथ स्वतंत्र गवाह की गैर-जांच चुन्नी और पर्स की बरामदगी को महत्वहीन बना देगी।[पैरा 41]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश (2005) 3 एससीसी 114:[2005] 1 एस. सी. आर. 1132; बदरुद्दीन

उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 300; जे. डी. जैन बनाम एस. बी. आई. के प्रबंधक (1982) 1 एस. सी. सी. 143:[1982] 2 एससीआर 227; यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम एयर 2000 एससी 1735:[2000] 2 एससीआर 1201; ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्न बनाम गुजरात राज्य

& ओआरएस। (2006) 3 एससीसी 374:[2006] 2 एससीआर 1081; चत्तर सिंह और अन्न. वी. हरियाणा राज्य (2008) 14 एस. सी. सी. 667:[2008] 12 एससीआर 765; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 सप्लीमेंट (4) एससीसी 259:[1995] 5 पूरक।एस. सी. आर. 10; अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 341:[2007] 7 एस. सी. आर. 983-निर्भर।

हट्टी सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2007) 12 एससीसी 471:[2007] 5 एस. सी. आर. 221-लागू नहीं होता है।

गोपाल और ओआरएस. वी. तमिलनाडु राज्य (1986) 2 एससीसी 93:[1986] 1 एससीआर 199; चत्तर सिंह और अन्न बनाम हरियाणा राज्य (2008) 14 एस. सी. सी. 667:[2008] 12 एससीआर 765; जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2009) 9 एससीसी 495:[2009]

14 एस. सी. आर. 727-संदर्भित। राज्य बनाम सुशील शर्मा 2007 (94) डी. आर. जे. 777 (डी. बी.)-अनुमोदित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1076-1077।

2002 के सी. आर. ए. सं. 685 और 671 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

हरियाणा राज्य 866 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

रूप:

प्रदीप गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, श्रीमती मानसी गुप्ता, राहुल कुमार चौधरी, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

दीपक ठुकराल, ए. ए. जी., गौतम शर्मा, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

सी. टी. रविकुमार जे.

1. अपीलार्थी, जो देविंदर उर्फ काला, पुत्र सुखबीर सिंह की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300 के साथ पठित धारा 34 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 201 के तहत भी दोषी ठहराए गए हैं और गलती से दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें सेशन केस No.121/99/2000 और सेशन ट्रायल No.17/2000 में उपरोक्त के रूप में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई और उनकी दोषसिद्धि और सजा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2002 के C. R. A. No.D-671-DB और 2002 के C. R. A. No.D-685-DB में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश के अनुसार स्वीकार किया गया।

2. अभियोजन पक्ष का मामला जो उपरोक्त रूप में उनकी दोषसिद्धि में समाप्त हुआ, इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

देविंदर @काला, एक 10+2 छात्र जो अपनी जमीन की सिंचाई करने गया था, 25.06.1999 से लापता पाया गया।आई. डी. 1 पर उनके भाई कृष्ण कुमार (पी. डब्ल्यू.-9) ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बाद में आई. डी. 2 पर उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने आठ लोगों का नाम लिया।, रणबीर, बलवान, राम कंवर, सतपाल, रामबीर, समुंदर, नरिंदर और पियारे, जिन्होंने कथित तौर पर उनके भाई का अपहरण कर लिया था।28.06.1999 को समयपुर बादली के पास पश्चिमी यमुना नहर पुल के नीचे एक युवक का शव तैरता हुआ पाया गया।शव को क्षत-विक्षत कर दिया गया था और दाहिने हाथ पर भगवान हनुमान का टैटू देखकर उनके भाइयों गोविंद और कृष्ण कुमार ने इसकी पहचान देविंदर के टैटू के रूप में की थी।एफ. आई. आर. No.220/99 शुरू में पी. एस. राय सोनीपत में आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत दर्ज की गई थी।अपीलार्थियों के नाम 867

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी.हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 868 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

इसका उल्लेख नहीं किया गया था।बाद में, पीडब्लू-10 मुकेश और पीडब्लू-8 आजाद के बयानों की रिकॉर्डिंग के अनुसार, आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 और 201 के तहत मामले जोड़े गए और इसमें अपीलकर्ताओं को आरोपी के रूप में आरोपित किया गया।

3. मामले के विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखते हुए यह उचित और प्रोफी टेबल है कि वे बनाए गए आरोपों को देखें और 15.11.1999 पर अपीलार्थियों को पढ़ें।वे इस प्रकार पढ़ते हैं:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“सबसे पहले:कि नाहरी गाँव के क्षेत्र में, आप दोनों ने अपने समान इरादे को आगे बढ़ाते हुए देविंदर पुत्र सुखबीर का अपहरण कर लिया ताकि उसकी हत्या की जा सके और इस प्रकार आप दोनों ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के तहत और इस अदालत के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

दूसरा:कि उक्त तिथि को रात को नाहरी गाँव के क्षेत्र में आप दोनों ने अपने समान इरादे को आगे बढ़ाते हुए जानबूझकर देविंदर पुत्र सुखबीर की हत्या कर दी और इस तरह आप दोनों ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत और इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

तीसरा:यह कि उक्त तिथियों, समय और स्थान पर आप दोनों अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए जानते हैं या यह विश्वास करने के लिए कारण हैं कि हत्या के अपराध के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, कुछ सबूत गायब हो गए, अर्थात्, कानूनी सजा से खुद की जांच करने के इरादे से शव को दिल्ली वाली नहर में फेंक दिया गया और इस तरह आप दोनों ने आई. पी. सी. की धारा 201/34 के तहत और इस अदालत के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।”

4. नतीजतन, उन पर उपरोक्त आरोपों में मुकदमा चलाया गया। आरोपों को संदर्भित करने की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर बाद में चर्चा की जाएगी। वृत्तचित्र के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के सत्रह गवाहों की गवाही वाले मौखिक साक्ष्य की सराहना करने पर, निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराया।

दोषियों द्वारा दायर अपीलों में, उनकी दोषसिद्धि और सजा को स्वीकार कर लिया गया था। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार पुत्र सुखबीर सिंह के नेतृत्व में दायर संशोधन, जिसे C.R.R.No.2242/2002 कहा गया था, उनकी अपीलों के साथ-साथ उनकी आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड में बढ़ाने की मांग को भी खारिज कर दिया गया। कृष्ण कुमार और जोगिंदर सिंह की अपील खारिज होने से व्यथित, दोषियों ने शीर्षक वाली अपीलों का नेतृत्व किया है।

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील और हरियाणा राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुना।

6. विवादित निर्णय और आदेश की जांच से पता चलता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि, जिसमें अंतिम बार देखे गए साक्ष्य, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, अवैध हथियार की बरामदगी और मकसद शामिल हैं, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी। लेकिन, उपरोक्त परिस्थितियों से निपटने से पहले इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या वे किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के बारे में किसी भी परिकल्पना को छोड़कर अपीलार्थियों के अपराध की ओर इशारा करते हैं, हम पहले इस बात पर विचार करेंगे कि क्या देविंदर की मृत्यु हत्या है और यदि ऐसा है, तो क्या यह गैर इरादतन हत्या है। 7. वास्तव में, शव की पहचान के खिलाफ और समवर्ती निर्णय के खिलाफ भी कोई चुनौती नहीं है कि देविंदर @काला की मृत्यु हत्या है और यह गैर-इरादतन हत्या है। पीडब्लू-4 डॉ. के. गोयल के साक्ष्य, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Ext.PD) के साथ उक्त निष्कर्ष पर आने के लिए नीचे की अदालतों द्वारा सराहना की गई थी। चिकित्सक की राय ई. एफ. ई. सी. टी. के लिए है कि मृत्यु का कारण गर्दन की संरचना पर दबाव, त्वचीय चोट, मांसपेशियों में चोट और हाइड्रड्रॉयों के कमजोर होने के परिणामस्वरूप दम घुटना है। वे अन्य पक्ष द्वारा गला घोटने की प्रक्रिया के दौरान गर्दन पर दबाव के कारण प्रकृति में पूर्व-शव परीक्षण थे। पीडब्लू-4 ने आगे कहा कि गर्दन की संरचना पर दबाव सामान्य समय में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। यह बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसलिए, यह समवर्ती निर्णय कि देविंदर @काला की मृत्यु हत्या है और यह गैर इरादतन हत्या का मामला है, उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण पर आया है, निर्विवाद है। 8. जब एक बार यह पाया जाता है कि मामले में शामिल मौत गैर इरादतन हत्या है, तो अगला सवाल यह होगा कि दोषी कौन है/हैं? यह स्थापित करने के लिए है कि अपीलार्थी अपराधी हैं और इसके लिए अभियोजन पक्ष ने 869 में निर्दिष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया था।

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 870

इससे पहले। जैसा कि यहाँ देखा गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी पाया गया था और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में पहली कड़ी 'अंतिम बार देखा गया' साक्ष्य है। 'परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में 'अंतिम बार देखा गया', यह स्थापित करने के लिए कम से कम एक गवाह की मौखिक गवाही के अस्तित्व का सुझाव देगा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी की संगति में देखा गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करना प्रासंगिक है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -9. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश 1 के निर्णय में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“अंतिम बार देखा गया सिद्धांत लागू होता है जहां उस समय के बीच का समय अंतराल जब आरोपी और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और फिर मृतक मृत पाया गया था, इतना कम है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का हिस्सा होने की संभावना असंभव हो जाती है। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होगा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था जब लंबे समय का अंतराल होता है और बीच में किसी अन्य व्यक्ति के आने की संभावना मौजूद होती है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था, किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, उन मामलों में अपराध के निष्कर्ष पर आना खतरनाक होगा।”

(जोर दिया गया)

10. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा हट्टी सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2 में दोहराया गया था। इस मुद्दे पर अधिकारियों के एक सर्वेक्षण से पता चलेगा कि इस स्थिति का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है। 'अंतिम बार देखे गए' सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें मामले में उपलब्ध अंतिम बार देखे गए साक्ष्य की जांच करनी होगी।

11. जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों से पूछताछ की गई थी और निर्विवाद तथ्य यह है कि उनमें से किसी ने भी आरोपी और मृतक को किसी भी विशेष समय पर एक साथ और जीवित नहीं देखा था। हम यह नहीं समझते कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा या विश्लेषण यह अभिनिर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि विचारण न्यायालय के निम्नलिखित स्पष्ट निर्णय को देखते हुए 'अंतिम बार देखा गया' सिद्धांत मामले में पूरी तरह से लागू नहीं था।

1 (2005)3 एससीसी 114 2 (2007) 12 एससीसी 471

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। फैसले के पैराग्राफ 10 में, ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार निर्णय दिया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“मान लीजिए कि मृतक को आखिरी बार कंपनी में नहीं देखा गया था

अभियुक्त ”।

12. जब अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही की सराहना पर निचली अदालतों का स्पष्ट निर्णय यह है कि किसी भी गवाह ने मृतक को आरोपी के साथ जीवित और एक साथ देखने की बात नहीं की थी, तो यह मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में तत्काल मामले में 'अंतिम बार देखे गए साक्ष्य' उपलब्ध हैं।

13. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर दिए गए इस तरह के स्पष्ट निष्कर्ष पर आने के बावजूद, स्पष्ट रूप से साक्ष्य की सराहना पर, निचली अदालत ने कुछ अन्य परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए, अपनी मृत्यु से ठीक पहले कटववाला मार्ग के पास चारा कक्ष में अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ मृतक की उपस्थिति का अनुमान लगाया। निर्णय के पैरा 13 में विचारण न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकेश, सरवन, आजाद देविंदर के शव के अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मृतक के साथ आरोपी के आखिरी बार देखे जाने के बारे में खुलासा नहीं किया। वास्तव में, आजाद, दया नंद, मुकेश और साहब सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर मृतक के साथ आरोपी को नहीं देखा है। लेकिन ऊपर चर्चा की गई सामग्री मृतक की हत्या से ठीक पहले आरोपी के साथ उपस्थिति दिखाने के लिए पर्याप्त है।”

(जोर दिया गया)

14. स्पष्ट रूप से, निचली अदालत द्वारा सकारात्मक साक्ष्य पर नहीं, बल्कि अन्य परिस्थितियों के आधार पर हस्तक्षेप पर तैयार की गई 'अंतिम बार देखी गई' की इस परिस्थिति का उच्च न्यायालय द्वारा विश्लेषण और सराहना नहीं की गई थी। जाहिरा तौर पर, इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या 'अंतिम बार देखे गए' की परिस्थिति परिस्थिति परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में उपलब्ध है, सबूतों की सराहना किए बिना, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-10 मुकेश, पीडब्लू-8 आजाद और पीडब्लू-7 दया नंद की मौखिक गवाही के आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार कर लिया कि मृतक देविंदर और पूनम की मुलाकात लगभग 25.06.1999 पर लगभग 08.30 पर कटववाला मार्ग के पास चारा कक्ष में हुई थी, वे अपीलकर्ता-दोषियों और 871 द्वारा एक आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे।

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 872 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

इसके बाद, अपीलार्थी-दोषियों ने पूनम से चुन्नी छीन ली और देविंदर की गला दबाकर हत्या कर दी, उन्होंने शव को एक बोरे में डाल दिया और चारा कक्ष के पास खड़ी राजदूत कार में रख दिया और शव को दिल्ली नहर के पास ले जाने पर उसे उक्त नहर में फेंक दिया गया।

15. यह उपरोक्त संदर्भ में है कि अपीलार्थियों के खिलाफ बनाए गए विशिष्ट आरोप, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, प्रासंगिकता ग्रहण करेंगे। जाहिर है, अपीलार्थियों के खिलाफ बनाया गया पहला आरोप, जैसा कि पहले यहाँ निकाला गया है, आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 364 के तहत था। आई. पी. सी. की धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश 'सामान्य इरादा' का तात्पर्य एक पूर्व-व्यवस्थित योजना और योजना के अनुरूप कार्य करना है। बदरुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“यद्यपि अभियोजन पक्ष के लिए सामान्य इरादे को स्थापित करना एक कठिन कार्य है, फिर भी, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होगा कि सभी हमलावरों की एक योजना या मन की बैठक थी, चाहे वह पूर्व-निर्धारित हो या पल भर में हो, लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध करने से पहले होना चाहिए।”

आई. पी. सी. की धारा 364 के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इस धारा के तहत एक अपराध स्थापित करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति का इरादा अपहरण या अपहरण के समय हत्या करने या हत्या के खतरे में डालने के लिए निपटाने का था। (फैसले को देखें)

गोपाल एंड ओआरएस. वी. तमिलनाडु राज्य) 4.

16. हमने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ बनाए गए पहले आरोप का उल्लेख केवल यह इंगित करने के लिए किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला, पहले आरोप के अनुसार, यह था कि अपीलार्थियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए देविंदर का अपहरण कर लिया था ताकि उसकी हत्या की जा सके। प्रासंगिक स्थिति में राज्य बनाम सुशील शर्मा 5 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय का उल्लेख करना उचित है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

3 (1998) 7 एससीसी 300 4 (1986) 2 एससीसी 93

5 2007 (94) डी. आर. जे. 777 (डीबी)

“यह अच्छी तरह से तय है कि आपराधिक मामलों में अनुमानों और अनुमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अभियोजन पक्ष से अपने मामले को स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि उसने प्रस्तुत किया है और यदि न्यायालय द्वारा किसी भी पहलू पर मामले पर अविश्वास किया जाता है तो न्यायालय अभियोजन पक्ष के लिए अपने दम पर एक नया मामला नहीं बना सकता है।”

17. हम उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत हैं। वास्तव में, सुशील शर्मा के मामले (ऊपर) में फैसले से उत्पन्न अपील में इस अदालत ने केवल फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। हम तत्काल मामले में इस तथ्य से अनजान नहीं हैं, हालांकि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित नहीं किया, जैसा कि सामने रखा गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालत ने अपने दम पर अभियोजन पक्ष के लिए एक नया मामला बनाया है। तत्काल मामले में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“हालाँकि, धारा 364/34 के तहत अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित नहीं किया गया है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया है। इसलिए, अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 364/34 के तहत अपराध से बरी कर दिया जाता है।

(जोर दिया गया) 18. यह एक ऐसा तथ्य है जो निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले से भी स्पष्ट होता है, जिसके तहत निचली अदालत के फैसले में कहा गया था कि इस पहलू पर कोई विचार नहीं किया गया था। यह इस मामले में निचली अदालत के फैसले से उपरोक्त पाठ से स्पष्ट है, हालांकि आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के तहत एक विशिष्ट सी आरोप तैयार किया गया था, अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश करने का विकल्प नहीं चुना था और इस तरह के मामले को वस्तुतः छोड़ दिया था। पीडब्लू 7 से 10 के साक्ष्य के आधार पर एक पूरी तरह से अलग मामला विकसित किया गया था और अंतिम बार देखे गए साक्ष्य, हथियार की बरामदगी के आधार पर साबित करने का प्रयास किया गया था।, चुन्नी, मकसद और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति। नतीजतन, हत्या करने के लिए अपहरण/अपहरण करने के सामान्य इरादे के आधार पर एक पूर्व-व्यवस्थित योजना के आरोप वाले मामले को हत्या के मामले में बदल दिया गया, जो कि अपीलार्थियों की बहन को कथित रूप से मृत देविंदर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर पल भर में हुआ था। संक्षेप में, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ

आई. पी. सी. की धारा 364/34 के तहत बनाए गए आरोप को स्थापित करने की परवाह नहीं की थी और इसके बावजूद उसने उपरोक्त के रूप में एक और मामला सामने रखा।

19. उपरोक्त बहुत ही असंवेदनशीलता के बावजूद, अदालतों ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण और सराहना करने के लिए उचित सावधानी और सावधानी नहीं बरती है।

873

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 874

हमारी टिप्पणी का कारण तत्काल मामले में किए गए साक्ष्य की सराहना के नंगे अवलोकन पर सामने आया। हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि यह साबित करने के बाद भी कि किसी ने भी मृतक को अंत में अभियुक्त के साथ नहीं देखा था, निचली अदालत ने माना कि जिन सामग्रियों पर चर्चा की गई थी, वे हैं -, पीडब्लू-7, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 का साक्ष्य मृतक की हत्या से ठीक पहले आरोपी के साथ उपस्थिति दिखाने के लिए पर्याप्त होगा। 20. पीडब्लू-10, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-7 की मौखिक गवाही और निचली अदालतों द्वारा उनकी सराहना के तरीके की सराहना करने से पहले हम इस सवाल पर विचार करना उचित समझते हैं कि क्या 'अंतिम बार देखा गया सिद्धांत', अपने आवेदन में, घटना से ठीक पहले आरोपी के साथ मृतक की उपस्थिति के बारे में अनुमान लगा सकता है, जैसा कि निचली अदालत द्वारा तैयार किया गया है, अभियोजन पक्ष के गवाहों के सकारात्मक नेत्र साक्ष्य के अभाव में कि उन्होंने मृतक को आरोपी के साथ एक साथ और घटना के निकट समय में जीवित देखा था।

21. हमें इसका नकारात्मक उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि अन्यथा किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में 'अंतिम बार देखे गए' के सिद्धांत का उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था, खतरनाक होगा, जैसा कि सतीश के मामले (उपरोक्त) में माना गया था। इसका अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग भी अस्वीकार्य है। इस संदर्भ में, हट्टी सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत के फैसले की भी प्रासंगिकता है। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक मृतक को अंतिम रूप से अभियुक्त व्यक्तियों के साथ देखा गया है और हत्या के बीच का समय अंतराल निकट नहीं है, तब तक केवल उसी आधार पर अभियुक्त के अपराध को साबित करना मुश्किल होगा। इसके अलावा, यह माना गया कि अंतिम बार देखा गया सिद्धांत लागू होगा जहां उस समय के बीच का समय अंतराल जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और मृतक को मृत पाया गया था, इतना कम है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाएगी। इन सबसे ऊपर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामले में भी न्यायालय को कुछ पुष्टि की तलाश करनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण को दोहराया गया था

चत्तर सिंह और ए. एन. आर. बनाम. मामले में निर्णय में न्यायालय। हरियाणा राज्य 6.

22. अब हम उन अन्य परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जिन पर अदालतों ने भरोसा किया था, वस्तुतः, यह अनुमान लगाने के लिए कि कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष में एक ही समय पर मृतक और आरोपी की उपस्थिति थी।

6 ए. आई. आर 2009 एस. सी. 378/(2008) 14 एस. सी. सी. 667

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

25.06.1999 की शाम। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा तैयार किए गए उक्त अनुमान की शुद्धता या अन्यथा पर चर्चा नहीं की थी और इस तरह के अभ्यास के बिना भी, दोषसिद्धि को स्वीकार करने के लिए अन्य परिस्थितियों पर भरोसा किया था। सबसे पहले, ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही पर भरोसा किया। पीडब्लू-10 मुकेश ने बयान दिया कि वह मृतक देविंदर का दोस्त था और लगभग 2 बजे जब वह देविंदर और एक सरवन के साथ सुखबीर सिंह (देविंदर के पिता) के घर (घर) में गपशप कर रहा था, तो देविंदर ने पूनम के साथ अपने प्रेम संबंध का खुलासा किया और उस दिन शाम को कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष में उससे मिलने के उसके वादे के बारे में भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 1 बजे जब वह अपने ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे, तो उन्होंने दोनों अपीलार्थियों को देखा।, जोगिंदर सिंह और कृष्ण कुमार चारा कमरे की ओर जा रहे हैं। हम यहां यह ध्यान देने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि पीडब्लू-10 के बयान की जांच से, हालांकि, पता चलेगा कि Ext.DD (उनके पिछले बयान) के साथ उनका सामना करने के बाद विरोधाभास/चूक जो अभियोजन मामले के मूल के खिलाफ हैं, उन्हें सामने लाया गया था। जैसा कि उस स्थान से संबंधित है जहाँ अपीलार्थियों को

लगभग 08.30 बजे 25.06.1999 पर जाते हुए देखा गया था, उन्होंने मुख्य परीक्षा के दौरान कहा कि लगभग 08.30 बजे तक फाइल से लौटते समय उन्होंने अपीलार्थियों को कटवाला मार्ग के पास चारा कक्ष की ओर जाते हुए देखा। हालाँकि, उसकी जिरह के दौरान Ext.DD के साथ सामना किए जाने पर यह पता चला कि 25.06.1999 पर लगभग 08.30 बजे अपीलार्थियों को 'कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष' के रूप में देखने का स्थान पुलिस को नहीं बताया गया था। इसे केवल एक चूक के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष के मामले के मूल के खिलाफ है कि मृतक देविंदर ने पीडब्लू-10 को बताया कि वह पूनम से प्यार करता था और उसने कटवावाला मार्ग के पास एक चारा कमरे में उससे मिलने का वादा किया था और बाद में, ऐसी घटना पर अपीलकर्ताओं ने कटवावाला मार्ग के पास चारा कमरे में गला घोटकर देविंदर की हत्या कर दी।

23. उपर्युक्त महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अब, पीडब्लू-10 के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या यह 'अंतिम बार देखे गए' सिद्धांत को लागू करने के लिए सकारात्मक साक्ष्य का गठन करता है और यदि नहीं, तो इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में 'अंतिम बार देखे गए साक्ष्य' को लेने को सही ठहराने के लिए अन्य सकारात्मक साक्ष्य क्या हैं। इस प्रश्न का समाधान साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 के आलोक में किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में प्रत्यक्ष होना चाहिए। हालाँकि, यह केवल 875 ही अस्वीकार्य है।

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 876

जब वह कथन की सच्चाई को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों द्वारा कथन के तथ्य को नहीं। अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी कथन के तथ्य को साबित करने और ऐसे कथन की सच्चाई को साबित करने के बीच कोई अंतर नहीं है। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा जे. डी. जैन बनाम एस. बी. आई. 7 के प्रबंधक के निर्णय में समझाया गया था। निर्णय के पैरा 10 में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“सुब्रमण्यम बनाम लोक अभियोजक, (1956) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 965 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा, "एक गवाह को दिए गए बयान का साक्ष्य, जिसे खुद गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, सुनी-सुनाई बात हो भी सकती है और नहीं भी। यह सुनी-सुनाई और अस्वीकार्य है जब साक्ष्य का उद्देश्य कथन में निहित सच्चाई को स्थापित करना है। यह सुनी-सुनाई बात नहीं है और स्वीकार्य है जब इसे साक्ष्य द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, न कि बयान की सच्चाई बल्कि इस तथ्य से कि यह किया गया था। यह तथ्य कि इसे इसकी सच्चाई से काफी अलग बनाया गया था, गवाह या कुछ अन्य व्यक्तियों की मानसिक स्थिति और उसके बाद के आचरण पर विचार करने में अक्सर प्रासंगिक होता है जिनकी उपस्थिति में ये बयान दिए जाते हैं।"

24. यह देखा जा सकता है कि पीडब्लू-10 ने केवल मृतक देविंदर के इस तथ्य के बारे में बात की थी कि वह पूनम से प्यार करता है और कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष में 25.06.1999 की शाम को उससे मिलने के उसके वादे के बारे में भी बात की थी। इसके अलावा, तथ्य यह है कि हालाँकि उन्होंने यह बयान दिया था कि उन्होंने अपीलकर्ताओं को यहां लगभग 08.30 बजे देखा था, लेकिन उन्होंने अस्पष्ट रूप से भी यह बयान नहीं दिया कि उन्होंने मृतक देविंदर और पूनम को घटना के निकट किसी भी समय एक साथ देखा था। हम पहले ही उसकी भौतिक चूक पर ध्यान दे चुके हैं। इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति के आलोक में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 को लागू करते हुए, भले ही यह माना जाए कि पीडब्लू 10 का साक्ष्य इस हद तक स्वीकार्य है कि मृतक देविंदर ने पूनम के साथ अपने प्यार और पीडब्लू-10 की शाम को देविंदर से मिलने के उसके वादे के बारे में खुलासा किया, पीडब्लू-10 के साक्ष्य को स्वीकार्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है जैसा कि उक्त कथन की सच्चाई से संबंधित है। यह साबित करने के लिए कि पूनम और देविंदर प्यार में थे और 25.06.1999 की शाम को वे वास्तव में कटवावाला मार्ग के चारा कमरे में मिले थे।

25. इस संदर्भ में, यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-10, जिसके साथ देविंदर ने अपने व्यक्तिगत रहस्य साझा करने का दावा किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उसने देविंदर के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया था। वह यह भी बयान देगा कि

7 (1982) 1 एस. सी. सी 143

वह देविंदर से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, उनका सबूत इस तथ्य के लिए है कि 03.07.1999 से पहले उन्होंने उपरोक्त तथ्यों के बारे में किसी को नहीं बताया था। इस मोड़ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह उसका विशेष मामला नहीं है कि वह पुलिस स्टेशन या जांच अधिकारी या किसी अन्य पुलिस अधिकारी के पास गया और अपने दम पर बयान दिया। ऐसी परिस्थितियों में सवाल यह है कि यह तथ्य कि उसे ऐसे मामलों की जानकारी/जानकारी थी, पुलिस के संज्ञान में कैसे आया। इस प्रकार, सभी कोणों से देखते हुए, यह देखा जा सकता है कि पीडब्लू-10 का साक्ष्य संदेह से मुक्त नहीं है और किसी भी दर पर, इसे 'अंतिम बार देखा गया' के सिद्धांत के अनुप्रयोग को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सकारात्मक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है या 25.06.1999 की शाम को अपीलार्थियों के साथ देविंदर की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए, इसे 'अंतिम बार देखा गया' साक्ष्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

26. पीडब्लू-8 आजाद पीडब्लू-10 मुकेश के पिता हैं। वह अदालत के समक्ष गवाही देगा कि लगभग आई. डी. 2 बजे जब वह अपनी जेल से लौट रहा था, तो उसने अपीलकर्ताओं को अपने कोठ से एक बोरे को निकालकर एक राजदूत में रखते हुए और उसे कटलापुर गांव की ओर ले जाते हुए देखा। उनके अनुसार हालांकि उन्होंने ऐसी घटना देखी थी, लेकिन जब तक उन्होंने पुलिस को बयान नहीं दिया, तब तक उन्होंने किसी को भी उक्त तथ्यों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मुकेश (पीडब्लू-10) उनका बेटा है और पीडब्लू-7 दयानंद उनका भाई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने इस सुझाव से इनकार नहीं किया कि उनके दादा जुग लाल और मृतक के पिता सुखबीर सिंह के दादा असली भाई थे और उन्होंने जो अपदस्थ किया था वह यह था कि वे असली भाई हो सकते थे।

27. पीडब्लू-8 के संस्करण की विश्वसनीयता का परीक्षण करते समय, कुछ पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत के समक्ष उनका पक्ष यह है कि उन्होंने आईडी2 पर लगभग आईडी1 बजे जिल सिंह और बलवान सिंह के भूखंड के पास एक पुरानी मॉडल सफेद राजदूत कार खड़ी देखी थी और आगे उन्होंने उस समय अपीलकर्ताओं को अपने कोठ से एक बोरे को निकालकर उक्त राजदूत कार में रखते हुए देखा था और उसे कटलापुर गांव की ओर ले गए थे। Ext.PB का सामना करने पर यह बयान सामने आया कि आरोपी द्वारा कार को कटलापुर गांव की ओर ले जाया गया था, पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। उनके बेटे पीडब्लू-10 ने अपदस्थ कर दिया कि लगभग 08.30 बजे जब वह जेल से लौट रहे थे, तो उन्होंने अपीलार्थियों को एक छोटे से रास्ते से गुजरते देखा था। इस प्रकार, उनके संस्करण एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। अगर वे वास्तव में अपने क्षेत्र से लौट रहे थे, हालांकि 877 के साथ नहीं

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 878

अन्य, और लगभग उसी समय विचाराधीन स्थान के पास पहुंचे।, लगभग 08.30 बजे 25.06.1999 पर उनके संस्करणों में इस तरह की विसंगतियां नहीं हो सकती थीं। हम दोनों ने अपने पिछले बयानों में किए गए सुधारों को भी देखा है, जो उनके साथ टकराव करके लाए गए थे। उनके संस्करण में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए मृतक देविंदर के भाई पीडब्लू-9 कृष्ण कुमार के मौखिक साक्ष्य का उल्लेख करना प्रासंगिक है। एफ. आई. आर. के अनुसार उनका मामला यह है कि उनके भाई देविंदर ने आई. डी. 2 की शाम को लगभग आई. डी. 1 बजे घर छोड़ दिया था। पीडब्लू-8, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-10 के संस्करणों की आगे की जांच करने से पहले पीडब्लू-4 डॉ. के. गोयल के साक्ष्य का उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक है जिन्होंने देविंदर के शरीर पर शव परीक्षण किया और Ext.PD तैयार किया।

पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट।

28. Ext.PD से पता चलेगा कि उसने 29.06.1999 पर 02.30 बजे देविंदर के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया था। उन्होंने कहा कि मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के समय के बीच का समय लगभग साढ़े तीन दिन है। इस प्रकार, मृत्यु के समय के बारे में उनकी राय के अनुसार यह 26.06.1999 पर 02.30 पूर्वाह्न में और उसके आसपास रहा होगा। यह सच है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शरीर बह रहा था और पानी में रह रहा था, मृत्यु के सटीक समय का पता लगाना संभव नहीं हो सकता है।

29. एक और पहलू है जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है। अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलेगा कि पूछताछ 28.06.1999 पर 10.30 पूर्वाह्न में की गई थी। जांच रिपोर्ट में कॉलम 17 शरीर की स्थिति के संबंध में है। जैसा कि इस सवाल से संबंधित है कि "क्या शरीर मोटा है या विघटित है" इसका जवाब इसके तहत दिया गया था।, "स्वस्थ और मजबूत, फ्लेश।" यह सच है कि अगले दिन किए गए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के अनुसार शव सड़ता हुआ देखा गया था। कम से कम, उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही पर संदेह करने के लिए पर्याप्त होंगी। मृतक देविंदर के साथ अपने संबंधों को

छिपाने के लिए जिरह के दौरान उनके टालमटोल वाले जवाब उनके बयान को और संदेह के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। पीडब्लू-10 इस संबंध में गवाही देगा कि यह कहना गलत होगा कि मृतक उसका चचेरा भाई था और आगे यह कहना गलत होगा कि उसके परदादा और मृतक देविंदर के परदादा जुग लाल थे। पीडब्लू-8, जो उनके पिता हैं, स्वीकार करेंगे कि उनके दादा जुडलाल थे और कहेंगे कि सुखबीर जो मृतक के पिता हैं, श्री राम के पोते हैं और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

जुग लाल और श्री राम असली भाई हो सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे। लेकिन पीडब्लू-9 कृष्ण कुमार, जो मृतक देविंदर का भाई है, अपनी जिरह के दौरान इस प्रकार गवाही देगा:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“इस मामले में बताए गए गवाहों सहित कुल परिवार के सदस्य दाह संस्कार के समय मौजूद थे अर्थात् आजाद और मुकेश भी मौजूद थे। इसके अलावा, पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही से पता चलता है कि उसने स्पष्ट रूप से अपदस्थ कर दिया था कि वह देविंदर के दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ था। पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 से उनके पिछले बयानों का सामना करने से सामने आए विरोधाभास, विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।”

30. प्रासंगिक स्थिति में, किसी को वास्तव में यह महसूस हो सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य को रोक दिया था, जिसके कारण उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता था। जाहिर है, इस सवाल के संबंध में कि क्या पूनम अपीलकर्ताओं की बहन है; क्या वह मृतक देविंदर से प्यार करती थी; यदि ऐसा है, तो क्या उसने देविंदर से कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष में मिलने का वादा किया था; क्या वे वास्तव में उस समय के करीब उक्त स्थान पर मिले थे; क्या अपीलकर्ता वहां पहुंचे और उसकी चुन्नी छीन ली और क्या उन्होंने उसकी चुन्नी का उपयोग करके मृतक का गला घोट दिया, सबसे अच्छी गवाह पूनम खुद होनी चाहिए थी। लेकिन तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष ने उससे पूछताछ नहीं की थी। जाँच के दौरान उससे पूछताछ के बारे में अभिलेखों से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस संदर्भ में जो बात अधिक परेशान करने वाली है, वह है निचली अदालत की यह टिप्पणी कि घटना के उद्देश्य को विकृत करने के लिए आरोपी द्वारा पूनम से पूछताछ नहीं की गई थी।

31. जब अभियोजन पक्ष एक उद्देश्य के साथ सामने आता है और उद्देश्य या तो साबित नहीं होता है या इसे अनुचित माना जाता है, तो उक्त तथ्य के गवाहों के साक्ष्य की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। ऐसा ही है।

यू. पी. राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित बाबू राम 8. ऐसा नहीं हो सकता

इस स्थिति के संबंध में संदेह है कि भारत में आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है, जिसके संबंध में अपीलार्थियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बनाया गया था। यदि अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छा सबूत पेश नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं मिला, इस अर्थ में, सबसे अच्छा गवाह जो अभियोजन पक्ष को अपना मामला स्थापित करने में मदद कर सकता था, तो केवल उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता था।

8 एयर 2000 एस सी 1735 879

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 880

अभियोजन पक्ष और निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित करने का कारण नहीं हो सकता है कि बचाव पक्ष उस उद्देश्य को विकृत/गलत साबित कर सकता था जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उस गवाह की जांच करके पेश किया गया था। ज़हिरा में निर्णय में हबीबुल्लाह शेख और अन्न बनाम गुजरात राज्य और अन्य। 9 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

इस प्रकार:

“साक्ष्य के कानून में यह एक प्रमुख नियम है कि सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60, 64 और 91 (संक्षेप में “साक्ष्य अधिनियम”) इस नियम पर आधारित हैं। संहिता के प्रावधानों के तहत अदालत को अभियोजन या बचाव पक्ष को अपने पक्ष के किसी विशेष गवाह या गवाह से पूछताछ करने के लिए मजबूर

करने का अधिकार नहीं है। यह पार्टियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन साक्ष्य का वजन करते हुए, अदालत इस तथ्य पर ध्यान दे सकती है कि सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य नहीं दिया गया है, और एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है।

32. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बचाव पक्ष का दायित्व/दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब अभियोजन पक्ष ऐसे मामलों में अपने बोझ का निर्वहन करेगा। पूनम से पूछताछ नहीं करके अभियोजन पक्ष ने वास्तव में सबसे अच्छे सबूत को रोक दिया था। शायद, उसकी जाँच करके यह मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में बदल गया होगा, यदि अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि कई प्रश्नों के संबंध में, वह प्रकाश डाल सकती थी।

33. अब, अन्य गवाहों की मौखिक गवाही से निपटने से पहले हम परिस्थितियों की श्रृंखला में उपरोक्त कड़ी से निपटना उचित और उचित समझते हैं।, 'मकसद', थोड़ा और। यह सच है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में उद्देश्य का महत्व होता है, लेकिन यह कहने का कोई कारण नहीं है कि उद्देश्य के अभाव में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। (जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य 10) में इस न्यायालय का निर्णय देखें। "अभिप्रेरणा" एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और यह सभी संभावनाओं में, प्रत्येक स्वैच्छिक कार्य के पीछे मौजूद होनी चाहिए। शुरु में, पीडब्लू-9 ने एक घटना का सुझाव दिया जो 29.05.1999 पर हुई थी। उनके अनुसार उस दिन उनके पिता सुखबीर सिंह और मृतक भाई देविंदर पर आठ लोगों ने हमला किया था और देविंदर किसी तरह भागने में सफल रहा था। लेकिन अपीलकर्ताओं को हमलावरों के रूप में नामित नहीं किया गया था

9 (2006) 3 एससीसी 374 10 (2009) 9 एससीसी 495

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उस घटना के संबंध में। हम यह समझने से चूक गए हैं कि यह एक मकसद कैसे हो सकता है। अपीलार्थियों का नाम भी संदिग्ध अपहरणकर्ताओं/अपहरणकर्ताओं में नहीं है। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी-दोषियों के खिलाफ जो मकसद पेश किया गया, वह यह है कि उन्होंने अपनी बहन पूनम को कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष में मृतक देविंदर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीडब्लू 7 के माध्यम से पेश किए गए अभियोजन पक्ष के अनुसार यह उद्देश्य था, सभी गवाहों के पूरे मौखिक साक्ष्य की जांच से पता चलेगा कि उनमें से किसी ने भी वास्तव में इस आशय से बात नहीं की थी कि उसने मृतक और अपीलार्थियों की बहन पूनम को या तो प्रासंगिक समय पर कटवावाला मार्ग के पास चारा कक्ष के अंदर या यहां तक कि किसी भी समय उपरोक्त स्थान के पास की घटना के निकट देखा था। वास्तव में, किसी ने भी घटना के दिन पूनम और देविंदर को एक साथ देखने के बारे में बात नहीं की थी, बहुत कम एक समझौता करने वाली स्थिति में। पी. डब्ल्यू.-7 दया नंद के समक्ष कथित रूप से उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर, वस्तुतः, उक्त उद्देश्य का आरोप अपीलार्थियों पर लगाया गया है। बेशक, अभियोजन पक्ष के अनुसार उद्देश्य भी अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के हिस्से के रूप में सामने आया था। हम कुछ समय बाद अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता या अन्यथा के बारे में बात करेंगे। अभियोजन पक्ष का मामला है कि उनकी बहन पूनम को उपरोक्त स्थान पर मृतक देविंदर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था, जिसने उन्हें उपरोक्त अपराध करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया कि पूनम वास्तव में अपीलार्थियों की बहन है या उनमें से कम से कम एक है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि पूनम बलवान सिंह की बेटी है, और पहला अपीलार्थी कृष्ण कुमार ओम प्रकाश का बेटा है और दूसरा अपीलार्थी जोगिंदर सिंह जिले सिंह का बेटा है। यह तथ्य, जो अभिलेख पर साक्ष्य से स्पष्ट है, निस्संदेह प्रकट करेगा कि वे भाई-बहन नहीं हैं और फिर, सवाल यह है कि उनके बीच रक्त की निकटता क्या है। वस्तुतः, अभियोजन पक्ष द्वारा उस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और वास्तव में, उस पहलू पर भी अभियोजन पक्ष केवल पीडब्लू-7 के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर निर्भर करता है।

34. जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा निर्भर परिस्थितियों की श्रृंखला में अगली कड़ी अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से पीडब्लू-7 को दी गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति है। यह सच है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को हमेशा साक्ष्य के एक कमजोर टुकड़े के रूप में और इस सवाल के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि क्या इसे 881 में स्वीकार्य के रूप में लिया जाना और दोषसिद्धि के लिए आधार बनाना योग्य है।

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 882 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

आपराधिक मुकदमा उस गवाह की सच्चाई पर निर्भर करेगा जिसके सामने कथित रूप से स्वीकारोक्ति की गई थी।

35. चत्तर सिंह और अन्न बनाम मामले में निर्णय में। हरियाणा राज्य 11

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर एक कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी से आगे निकल जाता है।

36. बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 12 के मामले में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

इस प्रकार आयोजित किया गया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“अपने स्वभाव से एक गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके लिए बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रशंसा की आवश्यकता होती है। जहाँ एक गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह अपना महत्व खो देती है।”

37. अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य 13 में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“8. हम सबसे पहले अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के दावे के संबंध में प्रश्न पर विचार करेंगे। हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि गवाह को सटीक शब्द बोलने चाहिए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण और भौतिक अंतर नहीं हो सकता है। अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के रुख पर विचार करते समय, अदालत को यह संतुष्ट करना होता है कि यह स्वैच्छिक था और बिना किसी जबरदस्ती और अनुचित प्रवाह के। अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है यदि वे व्यक्ति जिनके समक्ष यह कहा जाता है कि वे निष्पक्ष प्रतीत होते हैं और अभियुक्त के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं होते हैं। जहाँ शत्रुता दिखाने के लिए सामग्री है, अदालत को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या किसी अन्य साक्ष्य की तरह स्वीकारोक्ति गवाह की सत्यता पर निर्भर करती है जिसके सामने यह किया जाता है। यह अपरिवर्तनीय नहीं है कि अदालत को इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि वास्तविक शब्दों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाता है और सार दिया जाता है। यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि तथ्य स्वयं दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त है और अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के महत्व के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है,

11 ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 378; (2008) 14 एस. सी. सी. 667 12 1995 अनुपूरक (4) एस. सी. सी. 259

13 (2007) 12 एस. सी. सी. 341

साक्ष्य पर कार्रवाई की जा सकती है, भले ही सार और वास्तविक शब्द नहीं बताए गए हों। मानव मस्तिष्क एक टेप रिकॉर्डर नहीं है जो शब्द-दर-शब्द जो कहा गया है उसे रिकॉर्ड करता है। गवाह को अभियुक्त द्वारा बोले गए वास्तविक शब्दों को यथासंभव कहने में सक्षम होना चाहिए। यह किसी भी अस्पष्ट कथन की गलत व्याख्या की संभावना को खारिज कर देगा। यदि मामले के बयान की शब्द-दर-शब्द पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, तो अक्सर अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के प्रमाणिक मूल्य को अविश्वसनीय और उपयोगी नहीं होने के रूप में बाहर फेंकना पड़ता है। यह कानून की आवश्यकता नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास अच्छी स्मृति है और वे सटीक शब्दों को फिर से पोस्ट करने में सक्षम हो सकते हैं और ऐसे कई हो सकते हैं जिनके पास सामान्य स्मृति है और वे ऐसा करते हैं। यह अदालत को गवाह की क्षमता की विश्वसनीयता का न्याय करना है और उसके बाद यह तय करना है कि उसके साक्ष्य को स्वीकार किया जाना है या नहीं। यदि अदालत को विश्वास है कि जिन गवाहों के सामने स्वीकारोक्ति की गई है और संतुष्ट है कि स्वीकारोक्ति ऐसे साक्ष्य के आधार पर स्वैच्छिक थी, तो दोषसिद्धि स्थापित की जा सकती है। इस तरह की स्वीकारोक्ति स्पष्ट, विशिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए।”

38. पीडब्लू-7 दया नंद वह गवाह है जिसके सामने अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी। यह सच है कि दोनों न्यायालयों ने इसे स्वीकार्य माना और इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक मजबूत कड़ी के रूप में स्वीकार किया। पीडब्लू-7 दया नंद के बयान के अनुसार, इसमें अपीलकर्ता, (उनके द्वारा जोगिंदर और कृष्ण के रूप में नामित)

उनके पास तब आए जब वह अपनी बैठक में बैठे थे और उन्हें देविंदर पुत्र सुखबीर सिंह की हत्या के तथ्य, हत्या के तरीके और सबूतों को गायब करने आदि के बारे में बताया। वह अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान इस प्रकार गवाही देगा:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“आईडी1 पर मैं अपनी बैठक में बैठा था, इस बीच जोगिंदर और कृष्ण आरोपी मेरे पास आए और मुझे बताया कि उन्होंने सुखबीर के बेटे देविंदर की हत्या कर दी है और उसके शव को नहर में फेंक दिया है। अभियुक्तों ने मुझे यह भी बताया कि 25-6-99 पर वे ज़िले सिंह के चारा कमरे में गए, जहाँ उन्होंने देविंदर और पूनम को समझौता करने की स्थिति में पाया। उन्होंने पूनम को पीटा और उसे दूर भेज दिया लेकिन उन्होंने उसकी चुन्नी छीन ली और उसकी हरकतों के लिए देविंदर का गला घोट दिया और उसके शरीर को एक बोरे में डाल दिया। अभियुक्तों ने मुझे यह भी बताया कि शव को अपनी राजदूत कार में डाल दिया है और उसे दिल्ली नहर में फेंक दिया है। उन्होंने मुझसे यह भी अनुरोध किया कि सी. आई. ए. के कर्मचारी उनकी तलाश में हैं। इसलिए, वे मेरी मदद चाहते थे कि उन्हें 883 से पहले पेश किया जाए

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.] 884 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सी. आई. ए. कर्मचारी मेरे द्वारा जब मैं अदालत में मौजूद अभियुक्तों के साथ सोनीपत आया तो सी. आई. ए. के कर्मचारी मुझसे मिले और मैंने अभियुक्तों को उन्हें सौंप दिया। अभियुक्तों ने भी मेरी उपस्थिति में और साथ ही पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया।”

39. इसमें अपीलार्थियों के अपराध को मुख्य रूप से अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर घर लाने की मांग की गई थी। इसलिए, सवाल यह है कि क्या इस संबंध में पीडब्लू-7 के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करेंगे। इस प्रासंगिक पहलू पर विचार करते समय अभिलेख पर साक्ष्य से प्रकट कुछ कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जाहिर है, अभियोजन पक्ष के मामले को देखते हुए हत्या शाम को लगभग 08.30 बजे 25.06.1999 पर हुई थी। दिल्ली नहर से 28.06.1999 पर शव बरामद किया गया था और 03.07.1999 पर PW-8 आजाद और आजाद के बेटे, PW-10 मुकेश के बयान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे। हम पहले ही उनके संस्करण का उल्लेख कर चुके हैं। पीडब्लू-8 पीडब्लू-7 का भाई है और पीडब्लू-10 पीडब्लू-8 का बेटा है। पीडब्लू-7 का दावा है कि 09.07.1999 पर यहाँ अपीलकर्ता उसके पास आए और स्वीकार किया जैसा कि यहाँ पहले निकाला गया था। निचली अदालत के समक्ष 02.03.2001 पर उनसे पूछताछ की गई। उसकी मौखिक गवाही से पता चलता है कि वह मृतक देविंदर का ताऊ (चाचा) है और साथ ही उसके साक्ष्य की जांच से यह दिखाने के उसके कमजोर प्रयास का पता चलता है कि वह मृतक और आरोपी (यहाँ अपीलकर्ता) के समान संबंध रखता है। इससे पता चलता है कि वह अपीलार्थियों के साथ वास्तव में क्या संबंध है, इसके बारे में गवाही नहीं दे सकता था। उन्होंने अपदस्थ किया कि वह आरोपी जोगिंदर के दादा का नाम नहीं बता सकते थे। हालाँकि उन्होंने अपीलकर्ताओं के उनके पास आने की सटीक तारीख और घटना की सटीक तारीख को अपदस्थ कर दिया था, लेकिन उनकी जिरह से पता चलता है कि वह देविंदर की मृत्यु से संबंधित अधिकांश अन्य घटनाओं और मामलों से अनजान (या सच नहीं बता रहे) हैं। यह उनकी प्रतिपरीक्षा से निम्नलिखित पाठ से पता चलता है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कृष्ण और गोविंद ने मुझे बताया कि देविंदर का शव उन्हें मिल गया है। मैं देविंदर के अंतिम संस्कार की सही तारीख नहीं बता सकता, लेकिन मेरी उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई आजाद, उनके बेटे मुकेश और राम किशन के बेटे शरवन मौजूद थे या नहीं। मुझे नहीं पता कि दाह संस्कार के समय पुलिस मौजूद थी या नहीं। दाह संस्कार की अगली तारीख को भी मैंने पुलिस को नहीं देखा। मैंने नहीं देखा है

9-7-1999 से पहले पुलिस। अगर पुलिस गाँव में आई होती तो मैंने नहीं देखा होता। जब अभियुक्तों को पुलिस के सामने पेश किया गया, तब पी. डब्ल्यू. गोविंद ही मेरे साथ मौजूद थे। वहाँ और कोई नहीं था। नाहरी गाँव में बड़ी संख्या में दुकानें हैं। उस समय सभी दुकानें खुली थीं लेकिन कोई भी दुकान से बाहर नहीं निकला।”

40. इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-8 और पीडब्लू-10 के बयानों को दर्ज करने के बाद भी, जैसा कि उनके बयानों से पता चलता है, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अपीलार्थियों को कैसे पता चला कि देविंदर चारा कक्ष में था (यदि वे वहाँ थे तो भी) और मकसद क्या था आदि। अभिलेखों से प्रकट किए गए सभी उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन

निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था, हमारा विचार है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर पीडब्लू-7 का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं कर सकता है।

41. अब, हम अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में दूसरी कड़ी पर विचार करेंगे। यह हथियार की बरामदगी है।, गला घोटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चुन्नी। न्यायालयों के आदेश इस आशय के हैं कि इसे किसी सार्वजनिक स्थान से बरामद नहीं किया गया था। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वसूली के लिए एकमात्र स्वतंत्र गवाह श्री है। गोविंद, जो मृतक का भाई है, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। इसके अलावा, पीडब्लू-6 जो तत्कालीन इंस्पेक्टर, एस. एच. ओ., पीएस महम थे और फिर एस. आई. सी. आई. ए. कर्मचारी, सोनीपत के रूप में तैनात थे, ने कहा कि वह पीडब्लू-14 राम काला के साथ जांच में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पदच्युत किया

'चुन्नी' और पर्स की वसूली इस प्रकार:- “यह सही है कि इस प्रकार की चुन्नी और पर्स आमतौर पर बाजार में उपलब्ध होते हैं। चुन्नी और पर्स की बरामदगी के स्थान के पास एक सामान्य मार्ग है, जिसका उपयोग कई लोग करते हैं।

वह मार्ग और सभी के लिए सुलभ है।” पीडब्लू-14 ने उक्त वसूली के संबंध में यह भी कहा कि यह सही है कि वसूली का स्थान एक खुला स्थान है और सभी के लिए सुलभ है। उपरोक्त परिस्थितियों में पी. डब्ल्यू.-6 और पी. डब्ल्यू.-14 के बयान के साथ स्वतंत्र गवाह से पूछताछ न करने से चुन्नी और पर्स की वसूली अप्रासंगिक हो जाएगी। 42. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अभिलेख पर साक्ष्य का अध्ययन करने के बाद, जिसने हमें उपरोक्त टिप्पणियों, निष्कर्षों और निष्कर्षों को बनाने के लिए प्रेरित किया, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी साक्ष्य की पूरी तरह से विकृत तरीके से सराहना की है।, सबूत के वजन के खिलाफ। प्रत्येक 885 पर हमारे निर्णयों को देखते हुए

कृष्ण कुमार और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

परिस्थितियों की श्रृंखला में अपीलार्थियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 201, 300 और 302 के तहत कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। नतीजतन, सी. आर. ए. सं. में उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय। 2002 का डी-671-डी. बी. और सी. आर. ए. नं. 2002 का डी-685-डी. बी., जिसने सत्र मामले में निचली अदालत के फैसले और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा सत्र मुकदमे के फैसले को खारिज कर दिया। अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जाता है। चूंकि अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए उनके जमानत बांड जारी कर दिए जाते हैं। अपीलों की अनुमति ऊपर दी गई है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे